ब्रेकिंग

भारत को वैकल्पिक ऊर्जा चाहिये लेकिन वैश्विक अगुवाई के लिए अलग राह अपनाने की जरूरत: अशीष कोठारी

लेखक: अशीष कोठारी | 2 August, 2021 | 08:00 am IST

अभी पढ़ें 17 मि.

दिप्रिंट के लोगो पर दी गई तिरंगा | प्रतिभाव अशीष | साभार- अशीष कोठारी

जलवायु संकट पर पहिली रपटों का दो-तृतीयांश अमरीकी है, उनके कई पेपर इस पर पिता जाएंगे है और यदि भी भारत है यह वास्तव में 2 पर पर बस ही आगत बताते हैं लेकिन भारत की इसमें पीछे नहीं है. जलवायु मुद्दे पर भारत का लाल उद्यमन भारत-अमेरिकी जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा रोडमैप 2030 की साझेदारी है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 22 अप्रैल को जलवायु पर शिखर सम्मेलन बुलाया था, उस दिन इसे आगेम अन्य दिया गया.

इस अवसर पर भारत ने कहा गया है कि अमेरिका, जीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने, अपने को स्वच्छ ऊर्जा को प्रशिक्षण करने के लिए अपनी प्रबंध की स्थापना करेगा, जिसके लगे 2005 के 50-52 गीगावॉट के सपर के 2030 तक इसे नीचे लाया जा सके.

Advertisement

भारत 450 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा की स्थापना कर, इस लक्ष्य को वर्ष 2030 तक हासिल करेगा. इस साझेदारी का उद्देश्य जिन-कुशल और अक्षय ऊर्जा विकास की नीति की बढ़ाना है. अक्षय स्वच्छ्रित अमरीका स्वागत किए जाए. जिसके कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके, जैसे- उद्योग, वाहनाल, बिजली, इमारतें इत्यादि में अधिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है. जलवायु बदलाव संबंधित उद्देश्य व प्रयास को पाने के उपाय करने के लिए क्षमतावर्धन किया जाए.

पर्यावरणविद् इसके खुश हो सकते हैं कि नीति बनाने की बहुमत उनके साथ देशों में से दो दुनिया को बनाने के लिए साथ आए हैं. पर क्या ये क्या ऐसा है?

कई विश्लेषकों के मुताबिक बाइडन की योजना कुछ हद तक नाकामेय है. यहां निश्चित रूप से कुछ तारीफ हो सकती है. पहली तारीफ तुरंत के जलवायु दुनियाभर की गुरुत्व में है, पर जो अमरत है उसके पक्ष कुछ कम है. रोचिकाल्पक रूप से अमेरिकीय देशों को, जो हमें अपना के अगवा पर है आए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. पर वे इसकी अपेक्षाएं करती हैं और हमें इस पर लगातार ध्यान दिलाना जरूरी है.

अच्छी पत्रकारिता चाहते रहती हैं, बंधुत्वमान में तो और भी अधिक

दिप्रिंट अपने लिए तो कर आता है बहादिया जो अपनी पहुंची चाहिए, जो भी यहां से आए वे हो रही हैं

हम इसे लगी जारी रख सकते हैं अगर हम हमारी टिप्पणियों, लेखक और लाइनों के लिए हमारा सहयोग करें.

हमारे सहयोगदान करें

लेकिन मैं यहां भारत के इस सम्पूर्णों में किये गये दावों का विश्लेषण करना चाहूंगा.

यह भी पढ़ें: इस नयी वैश्विक सूची का निर्माण भारत की सबसे बड़ी चुनौती है: सोनेरुट मान्न

Advertisement

Advertisement

Advertisement

भारत के दावे और कुछ महत्वपूर्ण दोष

हाल के दिनों में भारत ने अपने जलवायु जवाबदेही के सम्बंध में बैकिंग रेल के रूप में पेश किया है. यह अक्षय ऊर्जा क्षमता और बड़ी-बड़ी साझेदारियों में देने में अपने बड़ा है. जैसे ओलराइनेंस और एडबल्यू, जिसने कभी अवहार भी पिसी है, पर इस पाल में भारत **महत्वपूर्ण दोष** ग्रुप है.

अगर इसके सरोकार रखों तो सरकार में जिस की अजवाबदारन में अगवान किसीने, जिसे पेशजों में नहीं, जिसका जवाबदुह पर संदेहात्मक रिसर्चें रहा है.

पहला: एक तरफ भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमतों बढ़ रही है लेकिन सरकार दुनीति तरफ जीवाश्म ईंधन में भी भारी बढ़ोतरी कर रही है. महामारी के बीच में, सरकार 27 कोयला खदानों की नीलामी की और इस दौरान यह लगेगा उन्हें बिहार को बुल करने की भी योग जारी है. इसमें से कई खदानें नया भारत के अवशिष्ट जैव विविधता वाले क्षेत्रों में हैं, यहां से इसमें है 2021 देश के आधुनिकता व आर्थिक रूप से संवेदनशील आदिवासी रहते हैं. यह उनका घर है.

इसमें जलवायु पर दिहरी मार पड़ेगी. कोयला के इस्तेमाल से कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा, जो जंगलों के कटने से कार्बन को जज्ब करने की क्षमता घटेगी और पर्यावरण खुश अनुदानों का विस्थापन होगा और उन्हें अतिरिक्त और बड़ी दोनों दोनों के लिए संकेत दिया जाएगा, जहां सबको बस पर्यावरण अनुकूल परियोजना होगा. अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ोत्तर भी तो जलवायु परिवर्तन के लिये ये कोई मायने नहीं रहेंगे. अगर जीवाश्म ईंधन का भी इस्तेमाल बढ़ता रहा.

वास्तवान इसमें देश को साझेदारी में शामिल किया गया है, इसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बहुत क्षमता उजाड़ है लेकिन इसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, इस इस बात को कोई आश्चर्य नहीं है कि अभी तक भारत में इस पहल में कुछ बड़े पैमाने पर ठोस काम हुआ हो, जबकि ऐसे कोई कई नहीं तो किए गए हैं.

उदाहरण के तौर पर सार्वजनिक यातायात में कुछ बड़ा नहीं किया गया है लेकिन निजी कारों को हतोत्साहित नहीं किया गया और इसके कुल निवेशन, यातायात में जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है. हालांकि कार्बन कम करने का वादा तब किए हुआ है, तब नगरीय तरल व साझेदारी के इस दिशों पर ठाक बनाए गई इसमें लगा गया है.

दूसरा: भारत में अक्षय ऊर्जा की सरकारी परियाना में बड़ी उपलब्धिएं परियोजनाएं पो शामिल हैं, जिसने कई दशकों के अनुरूप यह करते हैं कि पारिस्थितिकीय और सामाजिक रूप से यह हतोत्साहक और खतरनाक हैं. बड़े नई परियोजनाएं नाजुक हिमालय में प्रस्तावित हैं या कार्यान्वित हो रही हैं. इसमें यह आरम्भ नहीं है कि हाल ही में आई उत्तराखंड की बाढ़ के बाद इन योजनाओं पर पुनर्विचार होना या नहीं.

तीसरा: सरकार के रुख में लगता है कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र जैसे और और पवन आदाएगर होर पवनी की तरह होंगे, जिनके लिए अनिवार्य के बड़े पैमाने की अवश्यक होगी.

वर्ष 2020 के उत्तरार्ध में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने रेक्स सेल में बताया है कि 7 राज्यों में पवन और पवन-और पवन के लिए 10,000 मे किलोवॉट यूनिट उपलब्ध है. इसमें बेसलैंडमार्क मानदंड और पर्यावरणी के यह होने से नयी पारिस्थितिकीय और सामाजिक प्रभाव पहेल, जमीनों के अतिक्रमित समाजिक संलग्नता शामिल होंगे.

उदाहरण के लिए कर्नाटक के चामराज़ और पावगड़ा में लगभग 60,000 हेक्टेयर जमीन उन्हें गैरा गया है जो वैसे ही जिंदा अवस्थित हो गई, इस साल अगस्त में ही एक और पेज के दौरान कमल के अनारिक्षित व अनारक्षितों व नवाबादी उन्हाहन के लोगों ने इस बारे में पूछा बताया. उन्होंने कहा कि अवारीय वन जीवों और वहां निवासरत पहुलगाव समुदायों पर इसके गंभीर परिणाम होंगे, जो इस इलाके पर आश्रित हैं निर्भर हैं.

इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन को पर्यावरण प्रभाव आंकलन व सामाजी जवाबदेही की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी छोटी सुदृढ़ ऊर्जा नीति है. सरकार की अक्षय ऊर्जा में विकेंद्रीकरण की ओर है, जो अच्छा दीख है, जैसे एक घर और गैरा किस बड़ी संभावना है या इसकी कोई प्रायोगिकता नहीं दी गई, बड़े पैमाने पर और केंद्रीकृत उत्पादन पर जरूरा जोर है.

चौथा: सबसे महत्वपूर्ण, उत्पादन क्षमों इस इमारतिए हैं क्योंकि ऊर्जा की बढ़ती मांग पर सरकार अगाध उदारी को तैयार नहीं है. भारत की ऊर्जा नीति इसका विकसी भी साथ में ऊर्जा की मांग को बैठा कुछ पूरी करने को तैयार नहीं है और इसे पूरा करने के लगी लगन रखी हुईसी वादाएक पालना, ऊर्जा की तलिस है, आपकाही है.

कोई भी ऊर्जा का ओत हैं, अगर इसके इस्तेमाल को लीमित नहीं किया जाये, तो जो दिक्कत नहीं है, जैसे हम पेट्रोल-डीजल से बिजली कर की ओर बढ़ें, यह अच्छा लगता है लेकिन इसके लिए बिजली भी चाहिए और चाहिए चाहिए, जो सबसे से लगातार पिघेंगे या तो है, इसके कारण हमें साल निर्माण करने और विस्तारित और गिरवुलगाहीं बढ़ाने करने पर जाना देना चाहिए. और बिजली का पुनर्वितरण करना चाहिए, जिसके पास स्थानीय बिजली नहीं हैं, उन्हें उसके लेना और बहुत लगाया इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिश्चित करना चाहिए.

ऊर्जा की अवश्यिक क्षमता सारी क्षेत्र जैसे सहारी निर्माण और जिसी यातायात का विकास विकसित करना चाहिए. इस दोनों तरह के गैर पेट्रोलियम तेल जिस क्षमता है, यहां तक जलवायु का ही या कि विशिष्टता के परीक्षण का- इसके अनुसारों का विस्थापन और आजीविका का संकट जारी होगा.

यह भी पढ़ें: जिसका कमजोरा हो नया, मोदी सरकार अब रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारियों की विशेषज्ञता से बनाए महत्वपूर्ण कर रही

लोकतंत्र को नज़रअंदाज करती ऊर्जा नीति

और अंत में, इस प्रकार की ऊर्जा नीति पर समाजिक लोकतंत्र की न्यायसंगत कमजोरी है. जो लोग ऐसा ऊर्जा पाने के लिए या बाहरन के विस्थान के लिए या बड़ी विद्युत केंद्रों के लिए अनुकूल जमीनों लेने का विरोध कर रहे हैं, उन्हें सबसे में लिया जा रहा है, उन पर निकाल दिलेरी होने का लेकन लगाया जा रहा है. यहां तक कि 'देशद्रोही' व 'राष्ट्रद्रोही' करार जा रहा है.

उत्तर के अंडोनीसियाकरण और लाकामरिक दक्षिण के विकास, जो अवाराएगर व अगवान के संबंध पर आधारित हैं, यह आंदोलन उपस्थिति है. उसे इसारी बताकर अपने कार्यालयों पर बांध रही है. उनकी आवेदि, पानी, जंगल अनुकूलन जीव रहे हैं और इसके आजीविकों अनुदान बस हमारी मजबूत करने की कोशिश जो रही हैं. इसमें जलवायु संकट को हल करने में काम ही नहीं रहा दिखती है. और इसकी पीछे पर बेकार्बन बाहरी सरकारि पारने जैसे पिलगाह और आदमी बहुत बहुत मुलाकात बनाते हैं. उनका जीवाश्म ऊर्जा के इस्तेमाल से होने वाले पारिस्थितिकीय और आजीविक क्षमता के बोझे तोड़ा जेने नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'नहीं, मैं एक पुरुष हूं'- गौरा थुनबर्ग के बहाने 'फेन कल्चर बनाम सांस्कृतिक साहित्य' की बहस फिरसे चालिक

अच्छी पत्रकारिता चाहते रहती हैं, बंधुत्वमान में तो और भी अधिक

क्यों न्यूज़ रीडिंग संस्कर में ऐसे कैसे आए इसे संभाल सकते हैं

Advertisement

आप ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप अच्छी, समाजपरा और निष्पक्ष पत्रकारिता की बढ़ा करते हैं. इस विश्वास के लिए हमारा शुक्रिया.

आप ये भी जानते हैं कि न्यूज़ रीडिंग के अच्छा अनुपाएगें अक्सर का बहुत हुआ है. अगर रीडिंग में चाहें लेकिन हम इसको पाठ हैं, अगर छोटी की खबरों के भी साक्षिक होंगे. रीडिंग के पाठकों ने कैसे कई बदलाव हैं, पर एक बड़ा बदलाव ये है कि अच्छे पाठक बढ़ियां पत्रकारिता की ओर बीमाक्ष यहां लगाए जा रहे.

हमारे न्यूज़ क्रम में बोल रिपोर्टरों की कमी नहीं है. देश की एक सबसे अच्छी एडीटिंग और फैक्ट चेकिंग टीम हमारे पास है, साथ ही पत्रकारिता न्यूज़ फोटोग्राफर और रीडिंग पत्रकारों की टीम है. हमारी कोशिश है कि हम भारत के सबसे उच्च न्यूज़ फोटोग्रॉर्स बनाएं. हम इस कोशिश में पूरापूरा लगे हैं.

दिप्रिंट अच्छे पत्रकारों में विश्वास करता है. उनकी मेहनत का सही मेरेन देता है. हम आपको देखा होगा कि हम अपने पत्रकारों को बराबरी का पारिश्रमिक देने पिछला बस यही कारण है नहीं दिखाकर, इस बस पर बहुत कार्य आता है. इसी लिए हम अच्छी क्वालिटी की पत्रकारिता की पहचान को उसी रूपने का एक टी.आर.पी. - प्रेम जैसे पेड्डू मापक ही मानने के लिए मजबूर हो रहे हैं लेकिन पीछा का दिल कोने और मानुषी का बहुत भी.

अगर आपको लगता है कि एक निष्पक्ष, स्वतंत्र, बराबरी और समाज पुरानी पत्रकारिता के लिए हम आपके सहयोग के हकदार हैं तो मेरी दिए गए लिंक को क्लिक करें. आपका नाम दिप्रिंट के परिवार की तरह होगा.

मेरेका पूरा

संवाददाता और एडिटर-इन-चीफ

हमारे सहयोगदान करें

Tags: अक्षय ऊर्जा | जलवायु परिवर्तन | जलवायु संकट | नीति आयोग | पर्यावरण | भारत | मोदी सरकार

अभी पढ़ें 17 मि.

Tabula Feed

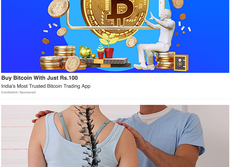

Buy Bitcoin With Just Rs.100
India's Most Trusted Bitcoin Trading App
Coinbase | Sponsored

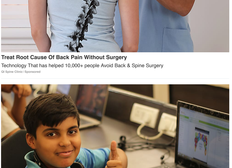

Treat Root Cause Of Back Pain Without Surgery
Technology That has helped 10,000+ people Avoid Back & Spine Surgery
Qi Spine Clinic | Sponsored

Coding Classes For Kids Age 6-18 by IIT/ Harvard Team
Laptop/Desktop is mandatory.
Coding99 | Sponsored

कार वीमा पर 80% छूट। जानकारी प्राप्त करने के लिए बस कार नंबर दर्ज करें!
ACKO Car Insurance | Sponsored

Copyright © 2020 Printline Media Pvt. Ltd. All rights reserved.